बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 133 ● नई दिल्ली ● सोमवार 09 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

### अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एएआई में महिला कर्मचारियों ने संभाली एटीसी की कमान, नारी शक्ति का दिखा दम

नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने एक महत्वपूर्ण पहल की। एएआई ने महिला कर्मचारियों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के संचालन की कमान सौंपी। यह कदम कार्यस्थल पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। एटीसी की प्रबंधक प्रांजलि टोलिया ने इस पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस जिम्मेदारी के लिए शुरुआत में कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। एयर ट्रैफिक नियंत्रक की पाली लगातार बदलती रहती है। काम के दौरान कई निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होता है।

## यूजीसी नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज, रामलीला मैदान, जंतर-मंतर से की ये मांग

नई दिल्ली । यूजीसी नियमों के खिलाफ रविवार को सवर्ण समाज दिल्ली की सड़कों पर उतरा। सवर्ण समुदाय के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें हाउस अरेस्ट करने के बाद भी बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के युवा दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पहुंचे और यूजीसी नियमों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। युवाओं ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी समाज और सभी वर्ग के हितों की रक्षा करे। युवाओं ने कहा कि नियम-कानून की आड़ में लगातार सामान्य वर्ग का उत्पीड़न होता रहा है, लेकिन अब बच्चों को कॉलेज स्तर पर भी प्रताड़ित करने की तैयारी की जा रही है। यह हर हाल में रुकना चाहिए। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने के बाद उनकी पुलिस जवानों से जमकर कहासुनी हुई। रामलीला मैदान में भी जोरदार प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर दूर ले गई।

सुरक्षा बलों का कहना था कि रविवार को यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी हजारों प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अयोध्या से सवर्ण आंदोलन में भागीदारी करने जंतर-मंतर पहुंची आरती तिवारी ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा और आरएसएस हमेशा हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, लेकिन यूजीसी नियमों ने हमारे बच्चों को ही अलग-अलग वर्गों में बांटने का रास्ता तैयार कर दिया है। बिहार के रणधीर सिंह ने कहा कि सरकार को केवल अमीर और गरीब दो वर्ग बनाने चाहिए। यदि छात्र गरीब है तो उसे बिना कोई भेदभाव किए सभी सुविधाएं देनी चाहिए। प्रयागराज से आए छात्र अमित शुक्ला ने कहा कि वे भाजपा या सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यदि सरकार ने यूजीसी नियमों को वापस नहीं लिया तो वे चुनावों का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि एक कानून बनाकर उन्हें अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मराज सिंह ने अमर उजाला से कहा कि पूरे देश में एससी/एसटी एक्ट का दुरूपयोग करते हुए सवर्ण समाज के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर पूरे-पूरे परिवार के साथ जेल में डाला जा रहा है। आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। लेकिन अब सवर्ण समुदाय के बच्चों को स्कूल कॉलेज में ही कानून के फंदे में फंसाकर जेल में डालने की साजिश रची जा रही है।

## हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, भाजपा ने कार्रवाई का स्वागत किया

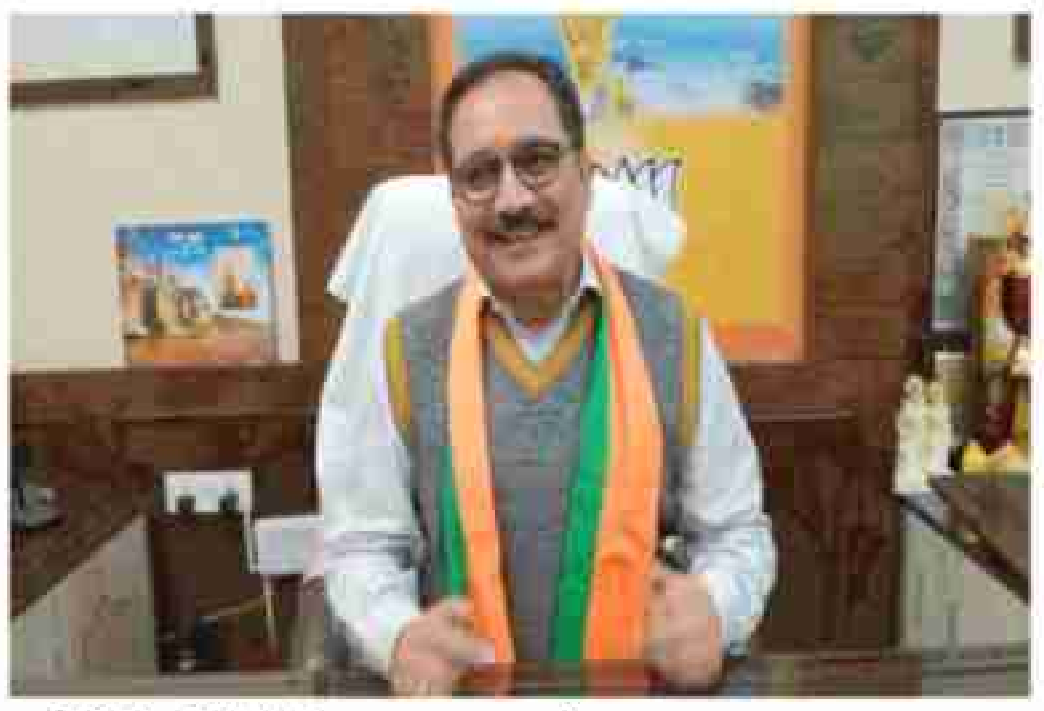

नई दिल्ली। होली के दिन उत्तम नगर में एक युवक तरुण की हत्या करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल गया है। अनधिकृत निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के अनुसार हुये इस ध्वस्तीकरण में रविवार सुबह ही बुलडोजर इस कॉलोनी में पहुंच गए। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में हुए इस ध्वस्तीकरण में अब तक मकान के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया है। आसपास के मकानों को किसी नुकसान से बचाने के लिए बाद में निगमकर्मियों ने हथौड़े का उपयोग करते हुए मकान के कुछ हिस्से को तोड़ा।

भाजपा ने इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने होली के दिन उत्तम नगर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे ऐसी हरकत करने वालों को कड़ा संदेश दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्व धर्म समभाव की संस्कृति वाले भारत देश में इस तरह की सांप्रदायिक सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें किसी एक समुदाय के लोग किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान न कर सकें। उन्होंने अभियुक्त परिवार का अवैध रूप से निर्मित मकान तोड़े जाने का स्वागत किया। सचदेवा ने कहा कि अतिवादियों ने पहले भी इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन अब इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तरुण की हत्या के आरोपियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर धर्म समुदाय के लोग आपसी भाई चारे को बनाए रखते हुए रहते आए हैं और दिल्ली को अपनी इस संस्कृति पर गर्व रहा है। इस संस्कृति को चोट पहुंचाने की किसी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि होली के दिन 4 मार्च को होली खेलने के दौरान एक बच्ची के हाथों रंग का गुब्बारा दूसरे समुदाय की एक महिला पर पड़ जाने से विवाद खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक साजिश रचकर तरुण को बुलाकर करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

## न्यायाधिकरणों पर बढ़ता बोझ - 5 लाख से अधिक मामले लंबित, पद खाली होने से बढ़ रही देरी

नई दिल्ली। अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए विभिन्न न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) अब खुद ही मामलों के भारी दबाव से जूझ रहे हैं। हालात यह हैं कि इन संस्थानों में लाखों मामले लंबित पड़े हैं और बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण मामलों का निपटारा धीमा हो गया है। कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के अलग-अलग न्यायाधिकरणों में कुल मिलाकर 5 लाख से यादा मामले लंबित हैं। इन मामलों की बढ़ती संख्या की सबसे बड़ी वजह अध्यक्षों, न्यायिक सदस्यों, तकनीकी सदस्यों और कर्मचारियों की कमी बताई जा रही है। मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 तक जारी आंकड़ों के अनुसार कई न्यायाधिकरणों में लगभग 18 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। स्थिति यह है कि सात न्यायाधिकरण ऐसे हैं जहां फिलहाल अध्यक्ष का पद ही खाली है। में अकेले 37 सदस्यों के पद खाली हैं। वहीं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) में भी 15 पद रिक्त बताए गए हैं। कई अन्य न्यायाधिकरणों में भी न्यायिक और तकनीकी पद लंबे समय से

खाली पड़े हैं, जिससे मामलों के निपटारे की गति प्रभावित हो रही है। न्यायाधिकरणों की व्यवस्था वर्ष 1976 में संविधान में किए गए 42वें संशोधन के जरिए लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक अदालतों, खासकर उच्च न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करना था। इन न्यायाधिकरणों की खास बात यह है कि इनमें न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। इससे उम्मीद की गई थी कि विशेष मामलों में विशेषज्ञता के आधार पर तेजी से फैसले हो सकेंगे और लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिन संस्थाओं को अदालतों का बोझ कम करने के लिए बनाया गया था, वही अब खुद समस्याओं का कारण बनती जा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कुछ मामलों में तो वित्तीय मामलों से जुड़े न्यायाधिकरणों के तकनीकी सदस्य फैसले लिखने का काम बाहर के लोगों से करवा रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायाधिकरण सरकार द्वारा बनाए गए निकाय हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी जवाबदेही स्पष्ट नहीं दिखती। अदालत के अनुसार कुछ न्यायाधिकरण ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं मानो वे किसी नो-मैन्स लैंड की तरह हों, जहां जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

### आपसी रंजिश में गोली मारकर युवक को उतारा मौत के घाट, बवाना इलाके में सनसनी

नई दिल्ली । बवाना इलाके में रविवार सुबह 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त पूठ खुर्द निवासी भूपेंद्र के रूप में हुई है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि सुबह में बवाना इलाके में स्थित राज वाटिका के पास एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक को गोली मारी गई है। पुलिस ने उसे तुरंत पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का शिनाख्त भूपेंद्र के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पता चला है कि भूपेंद्र के पिता बिजली कंपनी में काम करते हैं। वह बेरोजगार था। आशंका है कि आपसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है। पुलिस घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

## शुकराना कीर्तन समागम का आयोजन

नई दिल्ली. (अजय कुमार चौधरी) गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब स्थित लखी शाह बंजारा हॉल में शुकराना कीर्तन समागम का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। समागम के पश्चात संगत के लिए लंगर (भोज) की भी व्यवस्था की गई। यह आयोजन सिक्का ग्रुप के चेयरमैन सरदार गुरिंदर सिंह सिक्का की विवाह की स्वर्ण जयंती (50वीं वर्षगांठ) के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरदार गुरिंदर सिंह सिक्का ने बताया कि यह शुकराना समागम गुरु साहिब के आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद स्वरूप आयोजित किया गया है। समागम को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार हरमीत सिंह कालका ने भी संबोधित किया और संगत को गुरुवाणी के मार्ग पर चलने तथा सेवा और सिमरन के महत्व के बारे में प्रेरित किया। इस अवसर पर यमुनापार विकास बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली, पूर्व विधायक विपिन शर्मा, पूर्व निगम पार्षद गुरुचरण सिंह राजू, सिक्का ग्रुप के डायरेक्टर मयंक सिक्का व प्रणव सिक्का, झंकार ग्रुप के चेयरमैन महेश कपूर, हीरा स्वीट्स के प्रोपाइटर पारस शर्मा, राष्ट्र टाइम्स के संपादक विजय शंकर चतुर्वेदी, फेस ग्रुप के मुश्ताक अंसारी, समाजसेवी कैलाश अरोड़ा, विकास मार्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, सतवीर अग्रवाल, पियूष चौधरी, सतीश भट्ट सहित अनेक मंत्री, सांसद एवं गणमान्य लोग समागम में उपस्थित रहे।

## गीता कॉलोनी में 'गुरु मान्यों ग्रंथ चेतना समागम', खालसा साजना दिवस को समर्पित

पूर्वी दिल्ली . ( इंद्रजीत सिंह) के गीता कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान में आयोजित तीन दिवसीय 'गुरु मान्यों ग्रंथ चेतना समागम' खालसा साजना दिवस और वैसाखी की भावना को समर्पित रहा। धार्मिक वातावरण और संगत की बड़ी उपस्थिति के बीच आयोजित इस समागम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर गुरु परंपरा और सिख इतिहास के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।समागम के दौरान दीवान में भाई रणजीत सिंह ढडरियांवाले के आगमन पर कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक एवं पूर्व निगम पार्षद गुरचरन सिंह राजू ने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धार्मिक विचारों और कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं से जुड़ने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने भी विशेष रूप से भाग लिया। दोनों अतिथियों ने संगत से मिले स्नेह और सम्मान के लिए गुरचरन सिंह राजू का आभार व्यक्त किया तथा ऐसे आयोजनों को समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह बब्बर ने बताया कि तीन दिवसीय इस धार्मिक समागम को लेकर यमुनापार क्षेत्र की संगत में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि समागम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है और आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। समागम में संगत के लिए धार्मिक दीवान, कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना और समाज में आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करना है।

# पेड़ गिरवी रख कर कर्ज़ लेगी महाराष्ट्र सरकार

**महाराष्ट्र** सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है! कहा जा रहा है कि उसके पास अपने रोज़मर्रा के खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। इस वजह से उसे अपने पेड़ गिरवी रख कर कर्ज लेना पड़ रहा है। यह कोई मज़ाक की बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री गणेश नाईक ने यह जानकारी दी है। एक समय विजय माल्या ने अपने किंगफिशर ब्रांड की वैल्यू लगा कर उसके ऊपर कर्ज लिया था तो अदालत ने उसे धोखाधड़ी माना था। बहरहाल गणेश नाईक ने कहा है कि सरकार के सामने पैसे का संकट है, इसलिए पेड़ गिरवी रख कर कर्ज लिया जाएगा। असल में महाराष्ट्र में पिछले चुनाव के समय मुफ्त की 'रेवड़ी' बांटने वाले जो फैसले हुए उससे राज्य पर राजस्व का बड़ा बोझ पड़ा है। गणेश नाईक ने यह भी कहा कि 'लाड़की बहिन' योजना की वजह से सरकार पर बड़ा वित्तीय दबाव है। इन योजनाओं की वजह से सरकार की विकास की परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। यहां तक कि रूटीन के काम के लिए पैसे की कमी पड़ रही है। इसीलिए राज्य सरकार ने अपने सागवान के पेड़ गिरवी रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने सागवान के जो पेड़ लगवाए उनकी कीमत 12 हजार करोड़ रुपये के करीब आंकी गई है। उन पेड़ों को गिरवी रख कर सरकार छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी और उससे काम चलाएगी। अगर चुनावी लाभ के लिए नगद पैसा ट्रांसफर पर कोई सख्त नियम-कानून या नीति नहीं बनी तो पता नहीं राज्य सरकारों को क्या-क्या गिरवी रखना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर जनसभा की अनुमति हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बड़ी रैली करने की इजाजत मिल गई। हालांकि पहले दिल्ली पुलिस ने रैली करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि इजाजत दे दी गई। केजरीवाल ने वहां बड़ी रैली की। गौरतलब है कि केजरीवाल ने जंतर-मंतर से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। बहरहाल दिल्ली की विशेष अदालत ने पिछले दिनों उन्हें शराब नीति घोटाले में बरी किया है। उसके बाद अपने समर्थकों में उत्साह भरने के लिए केजरीवाल को तुरंत रैली करना था। रामलीला मैदान पर रैली इसलिए नहीं की क्योंकि वहां भीड़ जुटाने के लिए कई तरह के बंदोबस्त की जरूरत पड़ती। सो, उन्होंने जंतर मंतर पर रैली की अनुमति मांगी जो थोड़ी ना नुकुर के बाद दिल्ली पुलिस ने दे दी। दरअसल इस समय केजरीवाल जो भी मांगेंगे वह उन्हें मिलेगा, क्योंकि अगले साल होने वाले पांच राज्यों के चुनावों से पहले केजरीवाल को भाजपा विरोधी बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करना है। साथ ही कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को कांग्रेस से बनाए जा रहे इस नैरेटिव को ध्वस्त करना है कि राहुल गांधी सबसे सशक्त नेता हैं, मोदी पर हमला कर रहे हैं और इसलिए भाजपा से लड़ने वाला विपक्ष का चेहरा वे ही हैं। भाजपा चाहेगी कि केजरीवाल का चेहरा भी उभरे ताकि विपक्ष में फूट पड़े और कांग्रेस को अगले साल पंजाब, गोवा व गुजरात में नुकसान हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा झटका दिया है। अन्नाद्रमुक नेता ओ. पनीरसेल्वम को किसी तरह से एनडीए में लाया जा रहा था, लेकिन उनको लेकर दो तरह की समस्या थी। एक समस्या अन्ना डीएमके पर पूरा कब्जा करके बैठे ई. पलानीस्वामी थे, जिन्होंने साफ कर दिया था कि वे पनीरसेल्वम को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी ओर पनीरसेल्वम ने भी कह था कि पलानीस्वामी को नेता घोषित करके चुनाव लड़ा गया तो वे शामिल नहीं होंगे। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन से अपने तार जोड़ लिए थे। अब पनीरसेल्वम ने डीएमके का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि स्टालिन ने उनसे वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। पनीरसेल्वम ने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार किया था, जिससे मध्य व दक्षिण तमिलनाडु में कम से कम पांच सीटों पर भाजपा को फायदा हुआ था और वह दूसरे स्थान पर रही थी। पनीरसेल्वम थेवर समुदाय से आते हैं और मध्य व दक्षिण तमिलनाडु में बहुत असर रखते हैं। अब वे डीएमके से जुड़ गए हैं। वैसे भी डीएमके को दक्षिण तमिलनाडु में एक मजबूत नेता की जरूरत थी। पनीरसेल्वम ने वह कमी पूरी कर दी है। ध्यान रहे थेवर कभी भी डीएमके समर्थक नहीं रहे हैं। अगर उनका कुछ भी वोट पनीरसेल्वम ट्रांसफर कराते हैं तो डीएमके को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिन तक बिहार के सीमांचल की यात्रा पर थे। यह बहुत असामान्य बात है कि केंद्रीय गृहमंत्री किसी इलाके में इतना लंबा प्रवास करें। अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में भी रूके हैं लेकिन सीमांचल का मामला थोड़ा अलग है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर सीमांचल में कई बैठकें की थीं। इस बार भी उनके साथ केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शाह की उस यात्रा और उन बैठकों के बाद ही अलग राज्य की चर्चा तेज हुई। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है। लेकिन यह अनायास नहीं था। बंगाल चुनाव को ध्यान में रख कर देखने पर इसका महत्व समझ में आता है। भाजपा ने घुसपैठ को बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इसीलिए अगर यह चर्चा चलती है कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों खास कर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के कुछ हिस्से को मिला कर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों मालदा और उत्तरी दिनाजपुर के साथ जोड़ कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर बंगाल के मतदाताओं पर होगा। उत्तरी दिनाजपुर और मालदा दोनों किशनगंज और कटिहार से सटे हैं। अगर इन जिलों को मिला कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वहां बहुसंख्यक आबादी जम्मू कश्मीर जैसी होगी। वहां उप राज्यपाल और सीमावर्ती राज्य होने की वजह से सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके नियंत्रण रखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक बेवजह बिहार, झारखंड या उत्तर भारत की गोबरपट्टी के राज्यों की आलोचना करते हैं कि वहां पैसे बांट कर चुनाव जीता जाता है। लोग गरीब हैं इसलिए सरकारें मुफ्त की 'रेवड़ी' बांट कर चुनाव जीत जाती हैं।

# नेपाल में जेन-जी सरकार

पड़ोसी देश नेपाल में हुए आम चुनावों में वहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। चुनाव में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है। जबकि दशकों से सत्ता में रहे पारम्परिक दल बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। भारत विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. ?शर्मा ओली को अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही बालेन्द्र शाह से हार का मुंह देखना पड़ा है। के.पी. शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल), पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएम (माओइस्ट सैंटर) और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बालेन्द्र शाह जिन्हें बालेन शाह भी कहा जाता है, का प्रधानमंत्री बनना तय है। वह भारत के बेलगांव (कर्नाटक) से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर नेपाल की राजनीति में कूदे थे। वे एक लोकप्रिय रैपर और यूट्यूबर बने और फिर काठमांडू के मेयर बने। उन्होंने नेपाल की राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी है। बालेन्द्र उन प्रदर्शनकारियों में से थे जो सितम्बर 2025 में सड़कों पर उतरे थे और जेन-जी आंदोलन के कारण उस समय की के.पी. शर्मा ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। नेपाल का जनादेश नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। नेपाल की जनता को जेन-जी की नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। नेपाल में 19 मिलियन पंजीकृत मतदाताओं में से 60 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए वे वहीं थे जो पिछले साल के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान उभर गए थे। चुनावी मुद्दों में घोटाले, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, असमानता और कमजोर आर्थिक हालत शामिल रहे। हमारे आस-पड़ोस श्रीलंका और बांग्लादेश में भी किशोरों, नौजवानों ने अपने-अपने निज़ाम की चूलें हिला दी थीं और इन देशों में लोकप्रिय सरकारों का गठन हो चुका है। नेपाल तीसरा देश है जहां जेन-जेड की सरकार बन रही है। नेपाल की राजनीति में 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूर्य जरूर निकला मगर राजनीतिक स्थिरता मृगतृष्णा ही बनी रही। इस छोटे से देश ने 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते-जाते देखा और सत्ता की बंदरबांट को लगातार देखा। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड हों या शेर बहादुर देउबा, मधेसी आंदोलन से उपजे नए नेता हों या फिर के.पी. शर्मा ओली कभी विश्वासघात ने, कभी गठबंधन की जंग ने और कभी जनता के गुस्से ने प्रधानमंत्रियों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया। हर चेहरा सत्ता में आया लेकिन स्थिरता लाने में नाकाम रहा। औसतन हर 14, 15 महीने में नेपाल के लोगों को नया प्रधानमंत्री ?मिला। जनता ने सोचा था कि अब देश नई दिशा में आगे बढ़ेगा। गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, बुनियादी ढांचा सुधरेगा और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनेंगे लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्ट निकली। नेपाल में नया संविधान बनाने और उसको लागू करने में उथल-पुथल मची रही।

आंदोलनों का दौर चला। शासन में नेपाल के भारत से संबंध काफी तनावपूर्ण रहे और उन्होंने नेपाल को पूरी तरह चीन के हाथों गिरवी रख दिया था। भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बेटी के रहे हैं। हालांकि संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव भी आता रहा है। भारत न केवल नेपाल का निकटतम बाजार है, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, आपूर्ति और मौद्रिक स्थिरता का प्रमुख केन्द्र भी है। नेपाल के कुल व्यापार में नई दिल्ली के साथ व्यापार का हिस्सा लगभग 63 फीसदी है। जिसमें भारत उसके निर्यात का 68 प्रतिशत हिस्सा ग्रहण करता है। भारत ने हर संकट में नेपाल की सहायता ही की है। काफी हद तक नेपाल भारत पर निर्भर रहा है। नेपाल की सियासत में चीन का हस्तक्षेप बढ़ने से संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल की नई सरकार के भारत के साथ संबंध कैसे रहेंगे। बालेन्द्र शाह के कुछ पुराने बयानों ने भारत को चिंता में डाला था। 2023 में उन्होंने बालीवुड फिल्म में सीता को 'भारत की बेटी' कहने पर भारतीय फिल्मों पर बैन की मांग की थी, क्योंकि नेपाली परंपरा में सीता का जन्म नेपाल या नेपाल-बिहार बॉर्डर पर माना जाता है। उसी साल उन्होंने अपने ऑफिस में 'ग्रेटर नेपाल' का मैप लगवाया था, जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्र शामिल थे और इसे भारत के संसद में 'अखंड भारत' म्यूरल का जवाब बताया। वर्ष 2025 में एक पोस्ट में भारत, अमेरिका और चीन के खिलाफ गाली-गलौज वाली भाषा इस्तेमाल की, जिसे बाद में डिलीट कर दिया लेकिन हाल के महीनों में उनके रुख में बदलाव दिखा है। आरएसपी के मैनिफेस्टो से चीन की बीआरआई से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को हटा दिया गया, जो ओली के गढ़ झापा-5 में था। यह भारत के लिए राहत की बात है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से आरएसपी बैलेंस्ड विदेश नीति पर जोर दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शासन का सीमित अनुभव होने के कारण बालेन्द्र शाह की विदेश नीति कभी-कभी अप्रत्याशित हो सकती है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार को भारत और चीन के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। नई सरकार के पोलू रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था में सुधार, महंगाई नियंत्रण पर अत्याधिक ध्यान देना होगा। लोगों की चिंता का मूल कारण गहरी आर्थिक कमजोरी है। नेपाल की नाजुक अर्थव्यवस्था को नई सरकार किस तरह से सम्भालती है यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। भारत और नेपाल में कई संधियां हैं। पुरानी संधियों को लेकर भी कुछ मतभेद बने हुए हैं। नेपाल की नई सरकार को भारत के साथ संधियों को चाहे वह जल-विद्युत परियोजना हो या अन्य संबंध उन्हें विश्वसनीय अनुबंधों में बदलना होगा और भारत के साथ संबंधों को दिखावे की बजाय पेशेवर तरीके से प्रबंधित करना होगा। नेपाल की नई सरकार को चीन से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन पहले सहायता करता है फिर छोटे देशों को ऋण के जाल में फंसाता है, फिर उनकी भूमि हड़प लेता है। चीन ने श्रीलंका और अन्य देशों में ऐसा ही किया है।

**सम्पादकीय...**

# यूनिवर्सिटी हो तो गोटिया जैसी

**यूनिवर्सिटी** हो तो गोटिया जैसी हो, नहीं तो हो ही नहीं। जी हां आपने ठीक ही पढ़ा। मैं यही कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी गोटिया जैसी ही होनी चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जो विश्व प्रसिद्ध हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। ऐसी यूनिवर्सिटियां ही देश को विश्व गुरु बना सकती हैं। गोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा किया कि वह विश्व प्रसिद्ध हो गई। यूनिवर्सिटी ने पहले भी कोशिशें की थीं पर उनमें कोई न कोई कमी रह गई थी कि यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध नहीं बन पाई। पत्र पत्रिकाओं में पूरे पूरे पेज के, दो दो पेज के विज्ञापन छपवाये। उनके बल पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त किया पर वह बात नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। बहुत सारे पेटेंट भी रजिस्टर करवाए। ढाई तीन हजार तो करवा ही दिये होंगे। सारी महान प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इतने ही पेटेंट रजिस्टर करवाती हैं। जबकि किसी भी आईआईटी के पेटेंट कुछ सौ में ही होते हैं। तो इस मामले में भी गोटिया टॉप के विश्वविद्यालयों में रही। पर यह पराक्रम भी केवल विज्ञापनों में लिखने के काम ही आया। न तो प्रसिद्धि ही मिल पाई और न ही पेटेंट स्वीकृत हो पाए। विश्व की निगाहों से भी दूर ही रही। अपने छात्रों को सरकार की विरोधी पार्टी के प्रचार में भी भेज दिया। छात्रों को मुद्दा तक नहीं बताया गया पर अच्छे नंबर का भरोसा तो दिलाया ही गया होगा। कुछ पत्रकार ने छात्रों की बाइट ली और कार्यक्रम में चला दी। प्रसिद्धि तो मिली पर जरा कम रह गई। फिर आया एआई समिट। ग्लोबल समिट। नाम धांसू इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। समिट में प्रसिद्धि लायक बहुत कुछ हुआ। सरकार जी का फोटो सेशन हुआ। समिट में भाग लेने वाले लोगों के स्टाल से सामान चोरी हो गया। समिट एआई की थी पर वाइफाई नहीं था, इंटरनेट नहीं था। डिजिटल इंडिया में एआई समिट में डिजिटल लेन देन गायब था। घोर अव्यवस्था का आलम था। कांग्रेस का टी शर्ट उतार प्रदर्शन हुआ। इन सब की चर्चा तो हुई पर उतनी नहीं कि एआई समिट विश्व प्रसिद्ध हो पाती। इस समिट को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली गोटिया यूनिवर्सिटी से। खबर है कि चार पांच आईआईटीयों को मिला कर इतना बड़ा पेवेलियन नहीं मिला था जितना बड़ा अकेले गोटिया यूनिवर्सिटी को मिला। एआई के फील्ड में गोटिया ने काम ही इतना अधिक किया है कि इतना बड़ा पेवेलियन तो बनता ही था। गोटिया ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के लिए साढ़े तीन सौ करोड़ खर्च करने की बात कही। गोटिया यूनिवर्सिटी ने वह किया जो आजकल देश भर में हो रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पर हो रहा है। डिब्बे और लेबल अधिक बन रहे हैं, सामान कम बन रहा है। बाहर से सामान मंगवा कर उसे अपने डिब्बे में, अपना लेबल लगा फिट करना हो रहा है। सब यही कर रहे हैं और गोटिया ने भी यही किया। उसने चीन से एक रोबोट कुत्ता मंगवा कर उसे अपने यहां बना बता दिया। इससे एआई समिट को तो नहीं, गोटिया यूनिवर्सिटी को भी पूरे देश में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्धि मिली। तो देश की सरकार का, सरकार जी की सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षा की उन्नति के लिए, देश की प्रसिद्धि के लिए, जेएनयू, जामिया, जाधवपुर जैसे विश्वविद्यालयों को बर्बाद करे, आईआईटी और ऐसे उच्च संस्थानों में गोमूत्र और गोबर पर अनुसंधान करवाए और गोटिया जैसी यूनिवर्सिटी को सेंटर फॉर एक्सीलेंस घोषित करे।

# क्या नीतीश डिप्टी पीएम बनेंगे?

त्रिदीब रमण

**बिहार** के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही भाजपा के दबाव में बिहार से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया हो, पर उनका मन अब भी बिहार में ही रमा हुआ है, वे यहां से जाना नहीं चाहते। नीतीश समर्थकों का भी कमोबेश यही रुख है कि 'अगर बिहार की जनता ने उन्हें 2030 तक के लिए अपना 'मैंडेट' दिया है तो फिर वे बिहार छोड़ कर क्यों जाएं?' माना जाता है कि इससे पहले भी उन्हें भाजपा की ओर से उपराष्ट्रपति पद का ऑफर आया था, पर नीतीश ने इसके लिए मना कर दिया था। वे लगभग 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, उनकी पार्टी के 85 विधायक और 12 लोकसभा सांसद हैं, फिर वे 37 वर्षों बाद बिहार छोड़कर दिल्ली क्यों जाएं? यह भी माना जा रहा है कि 5 मार्च को यूं अचानक उनका राज्यसभा के लिए पर्चा भरना एक दबाव में लिया गया फैसला था, क्योंकि उसी रोज वे अपने पुत्र निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की एक बड़ी घोषणा करने वाले थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि नीतीश की जान अपने जिस पुत्र तोते में अटकी है। सूत्र यह भी इशारा कर रहे हैं कि रह-रह कर नीतीश का विरोध आकार ले रहा है। सो, अब दिल्ली ने भी दबाव की राजनीति छोड़ कर नीतीश के समक्ष एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली ने नीतीश को डिप्टी पीएम बनाने का प्रस्ताव दिया है अगर वे बिहार छोड़कर दिल्ली जाने को राजी हो जाते हैं। भाजपा की नज़र बिहार में नीतीश की परंपरागत वोट बैंक पर जमी है, जिसमें महिला वोटर, गैर यादव ओबीसी और लगभग 36 फीसदी ईबीसी आबादी शामिल है। अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना इस वोट बैंक को साधने का काम कर सकती है, पर एक संभावना यह भी है कि अगर नीतीश बिहार छोड़कर दिल्ली जाते हैं तो उनका ये वोट बैंक टूट कर-छिटक कर अन्य पार्टियों का रुख कर ले, सो भाजपा की योजना नीतीश के बेटे निशांत के लिए एक बिहार यात्रा निकालने की है जिससे उनके पिता के कैडर वोट पुत्र के पाले में आ सकें। वहीं नीतीश के करीबी नौकरशाह मनीष वर्मा नीतीश से यहीं कहते रहे कि वे अपनी जगह अपने पुत्र निशांत को राज्यसभा में भेज दें, पर बदली परिस्थितियों में नीतीश का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। बिहार के पूर्व गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को यूं अचानक उनकी विदाई की इबारत लिख दी गई या अपनी रुखसती का उन्हें पहले से इल्म था। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो आरिफ को कोई पखवाड़े पूर्व इस बात का अहसास हो गया था कि 'उनकी गवर्नरी छिनी जा सकती है', कहते हैं इसके बाद ही दक्षिण दिल्ली के एक अति संभ्रांत इलाके में अवस्थित उनके बंगले की रंगाई-पुताई शुरू हो गई, जब कुछ पत्रकारों को इस बात की भनक मिली तो आरिफ के नजदीकियों की ओर से उन्हें बताया गया कि 'दरअसल महामहिम (आरिफ) के लिए एक निजी लाइब्रेरी बनाने पर काम चल रहा है', महामहिम से जुड़े सूत्रों ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि 'फिलहाल उनका (आरिफ) दिल्ली वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है।' फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन अचानक बिना किसी नियोजित प्रोग्राम के आरिफ एक अनजान जगह के लिए छुट्टियों पर निकल जाते हैं। आरिफ को यह आश्वासन प्राप्त था कि बिहार के बाद उन्हें वेस्ट बंगाल भेजा जा सकता है, सो आरिफ के मन के किसी कोने में कतई इस संशय ने सिर नहीं उठाया होगा कि उन्हें एक झटके में यूं पैदल किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि इस बार बिहार में 'ऑपरेशन लोटस' की पूरी तैयारी थी, वहीं आरिफ अपने मूल में सियासत में पगे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको सियासी संतुलन साधने में महारथ हासिल थी। बिहार में भी उनकी लालू और नीतीश दोनों से बराबर की मित्रता थी, सो भाजपा को यह अंदेशा था कि अगर नीतीश को हटाने पर ज्यादा बवाल मचा तो बिहार में संक्रमण काल की उस राजनीतिक दौर में आरिफ पत्थर पर फूल खिलाने का काम कर सकते हैं, यानी वे लालू व नीतीश के बीच एक संवाद सेतु का कार्य कर सकते हैं, वैसे भी नीतीश को पलटने में सिद्धहस्ता हासिल है सो वे भाजपा के मारे एक बार फिर लालटेन की रौशनी में अपने सियासी भविष्य का 'रोड-मैप' तलाश सकते हैं। वहीं अगर बदले घटनाक्रम में जदयू में बड़ी टूट हो गई तो आरिफ भाजपा के लाभार्थी बनने की राह में खड़े नज़र आ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के नवनियुक्त गवर्नर सैय्यद अता हुसैन जो कि एक फौजी बैक ग्राउंड के हैं उनका ज्यादा यकीन 'रूलबुक' के हिसाब से चलने में हो सकता है, यही बात भाजपा के ज्यादा मुफीद है। वहीं इस मामले में आरिफ का नज़रिया कहीं ज्यादा स्वतंत्र और राजनीति अवलंबित हो सकता था, यह एक बड़ी वजह थी जिसने आरिफ की रुखसती की इबारत लिख दी। कोई चार वर्षों तक दिल्ली में उप राज्यपाली का जिम्मा संभाल रहे विनय सक्सेना को जिस जल्दबाजी में लद्दाख भेजा गया, राजनीतिक पर्यवेक्षक अब भी इसका सही कारण तलाशने में जुटे हैं, नहीं तो दिल्ली में भाजपा सरकार की वापसी का रोड मैप बनाने के लिए सक्सेना साहब ने क्या नहीं किया, भाजपा को दिल्ली में पुनर्स्थापित करने और जमी-जमाई आप सरकार को यहां से रुखसत करने में कोई भी उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंक सकता। खैर, चलिए बात करते हैं दिल्ली में सक्सेना साहब की जगह लेने वाले पूर्व भारतीय राजनयिक तरणजीत सिंह संधू की। जिन्हें संघ और भाजपा दोनों का ही बेहद लाडला माना जाता है। वे 2024 का लोकसभा चुनाव इस दफे भाजपा के टिकट पर अमृतसर से लड़े थे, पर जीत दर्ज करा पाने में नाकामयाब रहे। अमेरिका में भारतीय राजदूत रहे संधू साहब का दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नरी हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं। समझा जाता है कि उनके लिए इस दफे सबसे बड़ी लॉबिंग शिरोमणि अकाली दल के सर्वेसर्वा सुखबीर सिंह बादल ने की। यह भी कहा जाता है कि इस दफे अकाली दल व भाजपा को चुनावी गठबंधन के लिए तैयार करवाने में संधू की एक महती भूमिका रही। समझा जाता है कि संधू साहब की अब भी मौजूदा अमेरिकी प्रशासन से गहरे तार जुड़े हैं। सो, उनकी असली अग्नि परीक्षा भारत-अमेरिका के रिश्तों के उलझे पेंचोखम को सुलझाने की है, उनसे दिल्ली ने इस बारे में पहले से ही कहीं ज्यादा उम्मीदें पाली हुई हैं।

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां उन्हें 1100 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करना था। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड यात्रा का असली मकसद वहां भाजपा के विभिन्न गुटों में एका कराना और उन्हें आगामी चुनाव के लिए तैयार करना है। समझा जाता है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभयदान मिल गया है और यह भी एक तरह से तय कर दिया गया है कि प्रदेश में धामी विरोध की अलख चाहे जितनी भी सुलग रही हो पर वहां सीएम बदला नहीं जाएगा, यानी भाजपा धामी के नेतृत्व में ही एक बार फिर से आने वाले उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।

# नारी शक्ति का नया युग और वास्तविक चुनौतियां

**मानव** सभ्यता के विकास की कथा में यदि किसी शक्ति ने सबसे अधिक सृजन किया है, तो वह नारी शक्ति है। वह जीवन की जननी है, संस्कृति की वाहक है और समाज की संवेदनशील आत्मा है। भारतीय परंपरा ने नारी को केवल एक सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे 'माता' के रूप में सर्वोच्च आदर दिया। 'मातृदेवो भव:' की वाणी से लेकर 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की घोषणा तक हमारी संस्कृति में नारी के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय भाव दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत में धरती, गौ और मातृभूमि तक को 'माता' कहकर संबोधित किया गया। किन्तु विडम्बना यह है कि जिस समाज ने नारी को देवी का दर्जा दिया, उसी समाज में आज भी नारी असुरक्षा, भेदभाव और हिंसा का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमें केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि यह अवसर देता है कि हम नारी की वास्तविक स्थिति का गंभीर आत्ममंथन करें। विश्व स्तर पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि नारी की स्थिति में प्रगति अवश्य हुई है, किन्तु समानता, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की यात्रा अभी लंबी है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में लैंगिक समानता का लगभग 68.8 प्रतिशत अंतर ही समाप्त हो पाया है, अर्थात् अभी भी लगभग एक तिहाई अंतर शेष है। आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में यह अंतर सबसे अधिक है, जहां समानता केवल लगभग 61 प्रतिशत तक ही पहुंची है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि स्थिति बताती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो महिलाएं लगभग बराबरी के स्तर तक पहुंच गई हैं, परंतु आर्थिक अवसरों और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल कार्यबल का लगभग 42 प्रतिशत ही हैं और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर उनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। भारत में भी स्थिति मिश्रित है। एक ओर भारतीय महिलाएँ अंतरिक्ष, विज्ञान, सेना, राजनीति और प्रशासन में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम बाजार में उनकी भागीदारी अभी भी कम है। हाल के आँकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर लगभग 32 प्रतिशत है और बड़ी संख्या में महिलाएँ घरेलू दायित्वों के कारण रोजगार से बाहर रहती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के यह आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं, यह समाज की संरचना, सोच और अवसरों की असमानता को उजागर करते हैं। आज दुनिया के अनेक देशों में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और उद्योगपति के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। भारत में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक और फाइटर पायलट के रूप में महिलाओं की उपस्थिति इस परिवर्तन का प्रमाण बनी है और बन रही है। किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि दुनिया में अभी भी केवल सीमित देशों में ही महिलाएँ सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर हैं और समान वेतन का प्रश्न अभी भी अधूरा है। कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में औसतन कम वेतन मिलता है। एक और चिंताजनक तथ्य यह है कि संघर्ष, युद्ध और संकट की स्थितियों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। हाल के वैश्विक अध्ययनों के अनुसार 2024 में लगभग 67 करोड़ महिलाएँ ऐसे क्षेत्रों में रह रही थीं जो किसी न किसी प्रकार के हिंसक संघर्ष से प्रभावित थे। नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं। इतिहास के पन्ने यह भी बताते हैं कि जब-जब समाज संकट में पड़ा, तब-तब नारी शक्ति ने असाधारण साहस का परिचय दिया। स्वतंत्रता संग्राम में रानी चेनम्मा, बेगम हजरत महल, रानी अवन्तीबाई, सरोजिनी नायडू और दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाओं ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल करुणा की प्रतिमा नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस की भी प्रतीक है। लेकिन इतिहास के इन गौरवपूर्ण अध्यायों के बावजूद सामाजिक वास्तविकता कई बार पीड़ादायक दिखाई देती है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और यौन अपराध आज भी दुनिया के अनेक समाजों में मौजूद हैं। यह केवल कानून का नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता का प्रश्न है। दरअसल नारी समस्या का मूल कारण केवल बाहरी संरचनाएँ नहीं हैं, बल्कि वह सोच है जिसने सदियों तक नारी को 'कमजोर' मानकर उसकी क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया।

जब समाज नारी को केवल भूमिका से जोड़ता है, व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, तभी असमानता जन्म लेती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का वैश्विक संदेश भी इसी दिशा में संकेत करता है- ''सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और वास्तविक कार्रवाई।'' यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आज भी दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार पूरी तरह प्राप्त नहीं हैं और औसतन उन्हें पुरुषों के मुकाबले लगभग 64 प्रतिशत ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ कि यह स्थिति हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कानूनों को सामाजिक चेतना में बदलना भी आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल अधिकार देना नहीं है, बल्कि अवसर, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक भागीदारी, ये पाँच स्तंभ नारी सशक्तिकरण की वास्तविक नींव हैं। परंतु इस परिवर्तन की शुरुआत घर से ही होगी। यदि परिवार में बेटी और बेटे को समान अवसर मिलते हैं, यदि शिक्षा में भेदभाव समाप्त होता है, यदि विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाज स्वयं अस्वीकार करता है, तभी नारी की वास्तविक मुक्ति संभव है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा उन्हें गैस सिलिंडर दिलाना हो, गांवों में घरों और शौचालय का निर्माण हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पारित कराना। आज दुनिया के सभी देश इस बात को मान रहे हैं की मोदी के नेतृत्व में भारत की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत तक और राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा तक में महिलाएं बड़ी भूमिका में हैं। बात भारतीय या अभारतीय नारी की नहीं, बल्कि उसके प्रति दृष्टिकोण की है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण को बदलने की है, जरूरत सम्पूर्ण विश्व में नारी के प्रति उपेक्षा एवं प्रताड़ना को समाप्त करने की है। इस दिवस की सार्थकता तभी है

जब महिलाओं को विकास में सहभागी ही न बनाये बल्कि उनके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौंचने की वीभत्सताओं एवं त्रासदियों पर विराम लगे, ऐसा वातावरण बनाये। नारी को भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इतिहास गवाह है कि जब नारी ने अपने आत्मबल को पहचाना है, तब समाज की दिशा बदल गई है। शिक्षा और आत्मविश्वास नारी के लिए वही भूमिका निभाते हैं जो प्रकाश अंधकार के लिए करता है। आज की नारी केवल अधिकारों की मांग करने वाली नहीं, बल्कि परिवर्तन की निर्माता है। वह विज्ञान में शोध कर रही है, आकाश में विमान उड़ा रही है, संसद में कानून बना रही है, और समाज में नेतृत्व कर रही है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी सम्मान का प्रश्न केवल महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सभ्यता का प्रश्न है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सेक्टर पंचशील एन्क्ले. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/33862)

# मुस्लिम फ़ैडरेशन के रोज़ा इफ़्तार में जंगे बदर पर डाली रोशनी, मुल्क की सलामती की मांगी दुआ

मुरादाबाद।

पवित्र माहे रमज़ान के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया मुस्लिम फ़ैडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिफ हसन के जिगर कॉलोनी स्थित आवास पर रोज़ा इफ़्तार की महफ़िल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रोज़ेदारों और शहर के लोगों ने शिरकत की। रोज़ा इफ़्तार से पहले आयोजित तक़रीरी महफ़िल में उलेमा-ए-किराम ने रमज़ान की 17वीं तारीख़ की अहमियत और फ़ज़ीलत बयान की, इस अवसर पर चांद खां, आतीफ अहमद, ने ख़िताब करते हुए जंग-ए-बद्र की ऐतिहासिक अहमियत पर रोशनी डाली। उलेमा ने बताया कि रमज़ान की 17 तारीख़ को इस्लामी तारीख़ का अहम वाक़िआ जंग-ए-बद्र पेश आया था, जिसमें पैग़म्बर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 सहाबा के साथ हक़ और इंसाफ़ की ख़ातिर जंग लड़ी और अल्लाह

तआला की मदद से फ़तह हासिल की, उन्होंने कहा कि यह वाक़िआ सब्र, हिम्मत और स'चाई पर डटे रहने का पैग़ाम देता है, इतिहास गवाह है कि कामयाबी हमेशा हक़ और स'चाई की होती है। तारिक अनवर ने कहा कि जंग-ए-बद्र हमें यह तालीम देती है कि कोई भी जंग सिर्फ़ फौज की तादाद या जंगी साज़ो-सामान से नहीं जीती जाती, बल्कि ईमानदारी, स'चाई और अल्लाह की नुसरत से फ़तह हासिल होती है, उन्होंने कहा कि एक तरफ़ हुज़ूर-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 सहाबा थे, जबकि दूसरी तरफ़ विरोधियों की बड़ी और सुस'जित फौज थी, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई, सैयद आसिफ हसन ने मुसलमानों को नसीहत करते हुए कहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी ईमानदारी और नेक अमल के साथ गुज़ारनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, फेडरेशन के ज़िला महा सचिव व युवा लेखक फ़िरोज़ खां ने कहा कि अमन, भाईचारा और इंसानियत की ख़िदमत ही इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं, इस मौके पर मुल्क में अमन-चैन और सलामती के लिए ख़ास दुआएं की गई, दुआ के बाद सैकड़ों रोज़ेदारों ने सामूहिक रूप से रोज़ा इफ़्तार किया, कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम फैडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल समद चौधरी ने और संचालन साहिल शमसी ने किया। कार्यक्रम में मुस्लिम फैडरेशन के मंडलीय अध्यक्ष अतीक़ अहमद , जिला अध्यक्ष मुजाहिद पठान, महानगर अध्यक्ष फिरोज खान, डॉक्टर मेराजुल हसन,सलीम अहमद एडवोकेट, राष्ट्रीय लोक दल के महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली शाहनवाज मलिक जागरण बर खां, सैयद ज़ुबेर अली एडवोकेट इंजीनियर राशिद हुसैन, इकमान अली असलम परवेज़, मोहम्मद आरिफ, समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। ब्रो पेपर इस मौके पर मुस्लिम फेडरेशन के बानी हाजी नसीम अहमद एडवोकेट, अख्तर अहमद खान जनरललिस्ट, कौसर खान, अजीम इकबाल एडवोकेट की मगफिरत के लिए दुआ की।

# यूपीएससी में चयनित होने पर पीयूष एवं अंकित का किया सम्मान

मुरादाबाद। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बहुजन समाज में जन्मे मुरादाबाद के होनहार युवा पीयूष कुमार मौर्य एवं अंकित कुमार सिंह को बौद्ध जनकल्याण समिति द्वारा शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध का चित्र देकर सम्मानित कर हार्दिक बधाई दी गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विमल धीर ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है तथा युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है । अखिल भारतीय अंबेडकर संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन युवाओं की सफलता से समाज में शिक्षा, जागरूकता और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रति उत्साह को नई दिशा मिलेगी । प्रतिनिधि मंडल में व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के मुख्य संयोजक चंदन सिंह रैदास सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी दोनों सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित कर उनके उ'जवल भविष्य की कामना की । कार्यक्रम में विमल धीर महावीर प्रसाद मौर्य चंदन सिंह रैदास विनीत कुमार सागर जयप्रकाश सिंह मलखान सिंह रामपाल सिंह हेतराम सिंह आदि उपस्थित रहे।

# अखंड विश्वकर्मा महासंघ ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन

बहराइच।

अखंड विश्वकर्मा महासंघ के तत्वावधान में संगम पैरामेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर महासंघ के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएँ दीं तथा समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि होली का पर्व प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। सभी लोगों को मिल-जुलकर संगठन को मजबूत करते हुए समाज के उत्थान एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक डॉ0 गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव एडवोकेट दुर्गेश विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष अर्जुन शर्मा, गोंडा जिला अध्यक्ष जयलाल शर्मा, बहराइच जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, श्रावस्ती जिला अध्यक्ष डॉ0 अरविंद विश्वकर्मा, बलरामपुर जिला अध्यक्ष राज बहादुर शर्मा, संगठन मंत्री रामकुमार शर्मा व राधेश्याम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बहराइच प्रभाकर विश्वकर्मा व मगन विहारी, गोंडा जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनरेश शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष विजय शर्मा व प्रदीप विश्वकर्मा, मंडल सचिव विजय राज, महिला समाजसेविका निशा शर्मा, कार्यक्रम के आयोजक डॉ0 त्रिलोकी नाथ विश्वकर्मा, एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन द्वाराआयोजक डॉ0 विश्वकर्मा द्वारा अतिथियों एवं उपस्थित जनों के आभार व्यक्त करने के साथ हुआ।

# इनरव्हील क्लब के 'शृंगार उत्सव' में मुरादाबाद ईस्ट का दबदबा

मुरादाबाद।

इनरव्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 310 द्वारा मवाना में आयोजित डिस्ट्रिक्ट होली इवेंट शृंगार उत्सव हर्षोल्लास के साथ उत्सव मण्डप में संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न शहरों के क्लबों ने प्रतिभाग किया, जिसमें इनरव्हील क्लब मुरादाबाद ईस्ट की सदस्यों ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सम्मान समारोह रहा, जिसमें मुरादाबाद ईस्ट की वरिष्ठ सदस्य और पीडीसी वंदना गुप्ता को उनकी दीर्घकालिक निस्वार्थ सेवाओं और संस्था के प्रति समर्पण के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विभूषित किया गया। इस सम्मान पर क्लब की सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। उत्सव के दौरान आयोजित अन्य गतिविधियों में भी क्लब का भाग्य चमका। क्लब की अध्यक्षा वीना रस्तोगी ने लकी ड्रा का पुरस्कार अपने नाम किया, जिससे क्लब के खेमे में दोहरी खुशी छा गई। कार्यक्रम में क्लब की ओर से पीडीसी ममता गर्ग और पास्ट प्रेसिडेंट सीमा अग्रवाल ने भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया और अन्य जनपदों से आई सदस्यों के साथ होली की शुभकामनाएं साझा कीं।बताते चलें कि इससे पहले इनरव्हील क्लब मुरादाबाद ईस्ट की अन्य दो पीडीसी (ममता गर्ग एवं अनीता गुप्ता) को डिस्ट्रिक्ट चैयरमैन शालिनी गुप्ता द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मवाना में आयोजित इस शृंगार उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और फूलों की होली के बीच महिलाओं के सशक्तिकरण और आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया। मुरादाबाद ईस्ट की टीम ने इस सफल आयोजन के लिए डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया।

# इकबाल और उनके समकालीन कवि - जाबिर हुसैन सिद्दीक़ी

मुरादाबाद।

मीर, ग़ालिब और इक़बाल हमारे ऐसे शायर हैं जिनके कलाम और विचार-कला (फ़िक्र-ओ-फ़न) में वह आनंद, अंतर्दृष्टि, गहराई और मिठास है कि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसक है। ये तीनों कवि हमारे साहित्य के वे चमकते हुए रत्न हैं जिनसे वैश्विक स्तर पर काव्य - रसानुभूति और अंतर्दृष्टि के कारण लाभ उठाया जाता है। इनमें इक़बाल वह एकमात्र कवि हैं जिनके यहाँ दर्शन और उसकी एक व्यवस्थित प्रणाली भी मौजूद है। इस तरह उनकी शायरी में साहित्यिक सौंदर्य के साथ-साथ दार्शनिक तत्व अतिरिक्त मूल्य के रूप में शामिल हैं, जो उनकी शायरी को और अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इक़बाल के वैचारिक तंत्र में खुदी (आत्म-बोध) को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। खुदी स्वयं की पहचान या आत्म-ज्ञान के साथ-साथ ईश्वर की पहचान भी है। मनुष्य जब अपने अस्तित्व और अपनी क्षमताओं की समझ

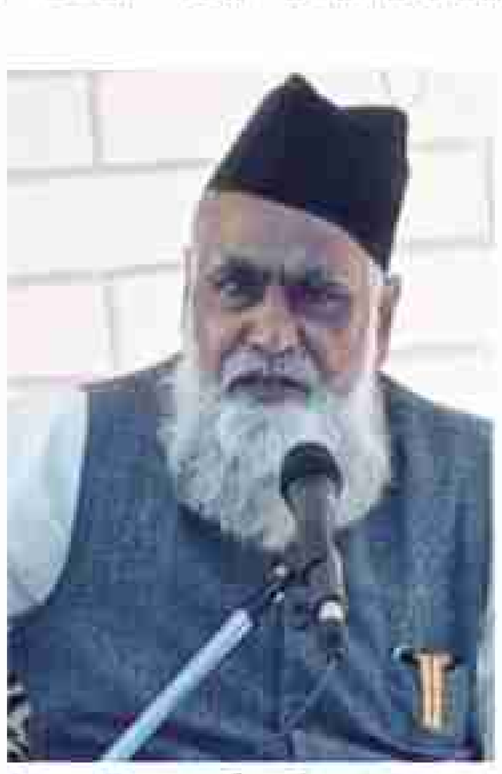

हासिल करता है, तो उसे अपने रचयिता (ख़ालिक) की समझ और पहचान भी प्राप्त होती है। इक़बाल के अनुसार व्यक्ति की मुक्ति आध्यात्मिक प्रशिक्षण और विश्वास की शक्ति (ईमानी कुव्वत) में है। खुदी की पुनः प्राप्ति और व्यक्तित्व के विकास के इक़बालिया संकल्पना का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व की समस्त संभावनाओं को प्राप्त करना, भटकाव और अवास्तविक व्यवहारों से व्यक्तित्व की रक्षा करना और उसका कल्याण है। इक़बाल सूफ़ियों की तरह स्वयं को एक तुछ बूंद नहीं समझते और उसे दरिया यानी ईश्वर की सत्ता में विलीन (फना) करने के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि उनके अनुसार मनुष्य एक मामूली बूंद के बजाय एक चमकता हुआ मोती है।इस विचार से मानवीय खुदी(अस्तित्व) बनी रहती है।

वे वहदतुल- वजूद (अद्वैतवाद) के कायल नहीं हैं; उनके निकट मानवीय खुदी ईश्वरीय सत्ता से पूरी तरह अलग है। वह ईश्वर के नूर (प्रकाश) से रोशन होती है

खुदी रोशन ज़-नूर-ए-किबरियाई अस्त,

रसाई पाए ओ अज़ नारसाई अस्त।

(अर्थ - ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है, उसकी पहुँच अपनी सीमाओं को पहचानने में ही निहित है।) इक़बाल ने खुदी की मजबूती के लिए कुछ साधन निर्धारित किए हैं, जिन्हें उन्होंने इश्क, निरंतर संघर्ष (जद्द-ओ- अमल), दृढ़ विश्वास (यकीन-ए- मुह्कम), फक्र (निर्लिप्तता), आत्म - निर्भरता (इस्तग़ना), न्याय और अन्याय की शक्तियों पर विश्वास और मुर्शिद-ए-कामिल (पूर्ण गुरु) के अनुसरण के नाम दिए हैं। एक व्यक्ति ईश्वर के प्रेम (इश्क-ए-खुदा) को सीने में बसाकर, निरंतर कर्मशील बनकर और फक्र-ओ-इस्तग़ना (सांसारिक साधनों की गुलामी के बजाय उन पर विजय) की दौलत हासिल करके और मुर्शिद-ए-कामिल यानी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अनुसरण के माध्यम से मर्दे-कामिल (पूर्ण मनुष्य) यानी मर्दे-मोमिन या बंदा-ए-हुर (स्वतंत्र व्यक्ति) बन सकता है।

इक़बाल के यहाँ खुदी की मजबूती के लिए सबसे प्रभावी तत्व इश्क है। यह एक हृदय का भाव है जो साधारण प्रेम से कहीं अधिक तीव्र है। उनके यहाँ स्वयं को जानने वाले व्यक्ति के लिए इश्क एक अनिवार्य गुण है। यह ब्रह्मांड की अनमोल पूंजी है। मानवीय बुद्धि नश्वर है और इश्क अमर है।

# राज्य कार्य योजना के तहत वृद्धजनों को मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएंः पंखुरी जैन

मुरादाबाद। जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना के घटक वरिष्ठ नागरिकों हेतु रा'य कार्य योजना संचालित की गयी है। वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजनों हेतु अनुमोदित गतिविधियां जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत उप निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में जागरुकता एवं सामुदायिक जुड़ाव समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा श्रेणी-3 के अन्तर्गत जागरुकता एवं सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्धारित अर्हताओं एवं चयनित संस्थाओं को आवश्यक एवं परिस्थितियों के अनुरुप कायान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संस्था के पास सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के किसी भी संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र, क्लीनिकल स्थापना एक्ट के तहत पंजीकृत अस्पताल के साथ एम.ओ.यू. अनिवार्य होना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन एवं स्वै'छिक संगठन के नाम से एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता होना चाहिए। संस्था का नीति आयोग के एनजीओ दर्पन पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र 01 जुलाई 2022 से पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य हो।

# कांग्रेस ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार पर साधा निशाना, NAAQS की समीक्षा पर दिया जोर

नई दिल्ली । कांग्रेस ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए 2009 के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (की तत्काल समीक्षा और उन्नयन किए जाने की रविवार को मांग की और जोर देकर कहा कि इन्हें अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। कांग्रेस के संचार मामलों के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम 56 इंच का पर्दाफाश हो गया है, पीएम 2.5 अब सच है। रमेश ने एक्स पर लिखा, पीएम2.5, यानी 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाला कण पदार्थ पूरे देश में गंभीर पर्यावरण-स्वास्थ्य संकट का कारण बन चुका है। उन्होंने दिसंबर 2024 में द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें 2009-2019 के बीच 655 जिलों के आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि पीएम2.5 सांद्रता में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के इजाफे से मृत्युदर में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि 2025 के लैंसेट काउंटडाउन के अनुमान के अनुसार, हर साल लगभग 17.2 लाख भारतीयों की पीएम 2.5 के संपर्क में आने से मौत हो जाती है, जो 2010 की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। रमेश ने यह भी कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2024, 2025 और 2026 में संसद को यह बताया था कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का कोई सटीक आंकड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण के अनुसार, 238 में से कोई भी शहर डब्ल्यूएचओ के पीएम2.5 के सुरक्षित मानकों का पालन नहीं कर रहा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, 238 में से 204 शहरों में पीएम2.5 सांद्रता 2009 में एनएएक्यूएस द्वारा निर्धारित स्तरों से ऊपर है। इसके बाद, डब्ल्यूएचओ ने सितंबर 2021 में अपने अद्यतन सुरक्षित मानक की घोषणा की। उन्होंने कहा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, 2009 की तत्काल समीक्षा और उन्नयन की आवश्यकता है। इन्हें हर जगह प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद निगरानी की जानी चाहिए। इसके अलावा, एनसीएपी को खुद पीएम2.5 पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

# मोदी की दिल्ली को 33,500 करोड़ की सौगात

नई दिल्ली ।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली मेट्रो के दो कॉरिडोर चालू हो गए हैं। इसमें से एक कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिल गई। वहीं, तीन अन्य कॉरिडोर की नींव भी रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रोजेक्टों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इसमें जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) पुनर्विकास योजना के अंतर्गत तैयार की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

**नई कनेक्टिविटी से दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा**

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 12.3 किमी का मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और लगभग 9.9 किमी का दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल हैं। नई कनेक्टिविटी से दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा, जिनमें बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क आदि शामिल हैं।

**पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला**

पीएम मोदी ने कहा, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि एक वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई, वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4

## देश की पहली रिंग मेट्रो राजधानी में शुरू

प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में तेजी आई है। आपदा वालों का तरीका था, काम कम और बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है, बहाने बंद, काम शुरू। पहले प्रोजेक्ट फाइलों में दम तोड़ते थे, आज प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज जो मेट्रो का नया सेक्शन शुरू हुआ है, उससे राजधानी के लाखों लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। खास तौर पर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए अब रोज का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। इन सबके साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में आना-जाना आसान हो जाएगा।

**आप-दा सरकार ने विकास का हर काम ठप रखा था**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, करीब 10 वर्षों तक आपदा सरकार ने यहां विकास का हर काम ठप रखा था। अब दिल्ली से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से अब लाखों गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी सरकार यमुना जी की साफ-सफाई के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है।

# भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां गौरव का स्रोत हैं - प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां गर्व का स्रोत हैं। मोदी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण उनकी सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं पहलों का मूल आधार है और सरकार ऐसे अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे प्रत्येक महिला अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सके और भारत के विकास की यात्रा में योगदान दे सके। उन्होंने एक संदेश में कहा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं हमारी समूची नारी शक्ति को शुभकामनाएं देता हूं। हर क्षेत्र में महिलाएं संकल्प, रचनात्मकता और बेजोड़ उत्साह के साथ भारत की प्रगति को आकार दे रही हैं। उनकी उपलब्धियां हमारे राष्ट्र को प्रेरित करती हैं और विकसित भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करती हैं। मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, महिलाओं की आकांक्षाएं और उनका योगदान एक मजबूत एवं समृद्ध राष्ट्र की दिशा में देश की सामूहिक यात्रा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा, भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां गर्व का स्रोत हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी परिवर्तनकारी भूमिका को सशक्त तरीके से याद दिलाती हैं।

## राष्ट्रपति के अपमान पर पीएम मोदी का टीएमसी पर हमला

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू संथाल के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं लेकिन राष्ट्रपति को सम्मान देने के बजाय, टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वे खुद आदिवासी समाज से आती हैं और वे आदिवासी समाज के विकास के बारे में चिंतित रही हैं। उन्हें सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया। यह न केवल राष्ट्रपति का अपमान है बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है। यह संविधान की भावना का अपमान है। यह लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। टीएमसी सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है।

# शिक्षित, सशक्त महिलाएं प्रगतिशील राष्ट्र की स्तंभ हैं - राष्ट्रपति मुर्मू

**महिलाओं में दम, हम नहीं हैं किसी से कम- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अनोखा संदेश**

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और अगर उन्हें सही अवसर और समर्थन मिले तो वे हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। रविवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि यह उनके सशक्तिकरण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, सशस्त्र बल, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, कला, खेल और उद्यमिता जैसे कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांवों की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और गांव के विकास में नेतृत्व भी कर रही हैं। मुर्मू ने आगे कहा कि महिलाओं में दम है, हम किसी से कम नहीं। हम में भी शक्ति है। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को अवसर और सहयोग मिले तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हालांकि महिलाओं ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के रास्ते में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों को सिर्फ कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाना भी जरूरी है। उन्होंने माता-पिता से अपील की कि घर में बेटियों और बेटों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सास को अपनी बेटी और बहू के बीच भी फर्क नहीं करना चाहिए और बहू को भी बेटी की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उनके अनुसार असली समानता तब शुरू होती है जब हर महिला को बेटी के रूप में सम्मान दिया जाए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित 'शक्ति वॉक' कार्यक्रम की भी सराहना की। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था, जिसमें प्रतिभागियों ने इंडिया गेट से विजय चौक तक पैदल मार्च किया।

उन्होंने देशभर से आई महिलाओं के समर्पण और उत्साह की भी प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर के प्रसिद्ध कथन को याद करते हुए कहा कि किसी समाज की प्रगति का सही मापदंड यह है कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।

## कमजोर पड़ रही भारत की वैश्विक मौजूदगी- पश्चिम एशिया युद्ध पर बोले संजय राउत

**पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल**

मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध को लेकर केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संकट के बीच भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी और भूमिका लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। राउत ने यह बात शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम 'रोकठोक' में लिखी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच बढ़े तनाव और अमेरिका की भूमिका के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई है और भारत एक देश के तौर पर इस स्थिति में पूरी तरह से अपना वजूद खो चुका है। राउत के मुताबिक, इस पूरे संकट में भारत को आगे आकर युद्ध रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बन चुका है। लेकिन भारत की तरफ से इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने भारतीय नेतृत्व की कमजोरी भी उजागर हो रही है। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है।

**अमेरिका और इसराइल पर भी बोला तीखा हमला**

संजय राउत ने अमेरिका और इसराइल पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और इसराइल दुनिया में दबंगई दिखा रहे हैं और खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं। राउत के अनुसार, इन देशों को लगा कि वे ईरान को बहुत आसानी से हरा देंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका को लगा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। युद्ध के दौरान ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी मारे गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान लगातार जवाबी हमला कर रहा है और युद्ध जारी है।

ये भी पढ़ें- पश्चिम एशिया में युद्ध का भारत पर क्या असर- तेल-गैस के लिए क्या कदम उठाए गए, संघर्ष में अब तक क्या रही भूमिका?

**ग्लोबल बुली की तरह व्यवहार का आरोप**

राउत ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इसराइल दुनिया के ग्लोबल बुली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देश, जो पहले अपनी बहादुरी की बात करते थे, अब इन देशों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अपने लेख में राउत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच भारत को मजबूत और स्वतंत्र रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका कमजोर नजर आ रही है।

# ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम पर सहमति

**फिलहाल ऐलान नहीं, इजराइल बोला- खामेनेई के हर उत्तराधिकारी को निशाना बनाएंगे**

तेल अवीव/तेहरान ।

ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम पर सहमति बन गई है। फिलहाल नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उम्मीदवार तय कर लिया है। असेंबली के सदस्य मोहसिन हैदरी ने कहा कि बहुमत से सबसे योग्य उम्मीदवार के नाम को मंजूरी दी गई है। संस्था के एक अन्य सदस्य मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी ने भी इसकी पुष्टि की है। दूसरी तरफ इजराइली सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के हर संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। आईडीएफ ने कहा कि उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में शामिल लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है। संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट में खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई का नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि ट्रम्प ने कहा है कि वे मुजतबा को नए सुप्रीम लीडर के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे।

**जंग के 5 बड़े अपडेट्स**

ईरान में अब तक 6,668 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 5,535 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर भी हमला किया गया। यूएस-इजराइल और ईरान जंग में अब तक 1701 मौत हुई है।जंग में अब तक इजराइल के 1765 लोग घायल हुए हैं।

# नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू जॉइन की, बोले- पापा पर भरोसा रखिए, उनके काम को आगे ले जाऊंगा

पटना ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता दल युनाईटेड में शामिल हो चुके हैं। वीर चंद पटेल रोड स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। जदयू में शामिल होने के बाद निशांत ने कहा कि मैं जदयू के कार्यकर्ता, नेता और बिहार की जनता को नमन करता हूं। मैं आज से पार्टी का सदस्य बन चुका हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा करता रहूंगा। मेरे पिता ने राज्यसभा जाने की घोषणा की है। यह उनका निजी फैसला है। मैं इस फैसले का आदर करता हूं और इसे स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता से अपील करता हूं कि पिताजी पर विश्वास बनाए रखें। निशांत कुमार ने कहा कि मेरे पिता ने बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, उसे मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप सब ने जो विश्वास किया, उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। जनता के हृदय में खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे पिता ने जनता के लिए जो किया, वह सबको याद रहेगा। जनता को मेरे पिता पर गर्व है। वह अपना जीवन बिहार के लिए समर्पित कर दिया। आज से मैं राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। इसके लिए मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए। मैं आप सभी को नमन करता हूं।

# भारत तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड चैंपियन

**पहली बार मेजबान टीम ने खिताब जीता, फाइनल में रिकॉर्ड 255 रन बनाए, न्यूजीलैंड की 96 रन से सबसे बड़ी हार**

नई दिल्ली । भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है. फाइनल मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है.

भारत ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड किया है. अहमदाबाद में खेले गए इस फाइनल मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 255 रन बनाए थे, जवाब में कीवी टीम 159 रन ही बना सकी.

**भारतीय टीम ने रचा इतिहास**

अब तक वेस्टइंडीज और इंग्लैंड भी 2-2 बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को 3 बार जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है. टीम इंडिया ने 2007, 2024 और अब 2026 का खिताब जीता है. इससे पहले कोई भी टीम लगातार 2 बार टी20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी. भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भी पहला देश बना है.

**बनाया था फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर**

भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने आई थी. संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में अर्धशतक लगाया. सैमसन ने 89 रन बनाए, जो इस वर्ल्ड कप में उनकी लगातार तीसरी अर्धशतकीय पारी रही. वहीं अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 18 गेंद में पचासा जड़ा. ईशान किशन ने भी 25 गेंद में 54 रनों का योगदान दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए थे.

**इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और कहा कि इस जीत ने हर भारतीय को गर्व और खुशी से भर दिया है।**

यह टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा. इससे पिछला रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम था, जिसने 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में 176 रन बनाए थे. अब टीम इंडिया ने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 255 रन बनाए.

**96 रनों की जीत**

256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई न्यूजीलैंड की टीम कभी जीत की रेस में थी ही नहीं. टिम सहफर्ट के 52 रन और कप्तान मिचेल सैंटनर की 43 रनों की पारी के अलावा कोई भी कीवी बल्लेबाज प्रभावशाली पारी नहीं खेल पाया. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, जिन्होंने कुल 4 विकेट झटके. वहीं अक्षर पटेल ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया. उनके अलावा हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने भी एक-एक विकेट लिया.